दैनिक जागरण

समाधान अक्सर समस्या के इर्द-गिर्द ही होता है

फिर वही पराली दहन

यह हैरान करता है कि बीते वर्षों में तमाम चिंता और चेतावनी जताए जाने के बाद भी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों और खासकर पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि इन राज्यों में पराली जलाए जाने की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, लेकिन ऐसा तो बीते वर्षों में भी होता रहा है। सर्दियों की आहट मिलते ही केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी भी पराली जलाने के खिलाफ सक्रिय हो उठता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहता है। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बैठक होती है तो भी इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर भारत आसमान में छाने वाले धूल और धुएं के गुबार से बच सकेगा। हालांकि सभी इससे भली तरह परिचित हो चुके हैं कि धूल और धुएं के जहरीले गुबार से बना स्मॉग आम आदमी की सेहत के लिए गंभीर संकट पैदा करता है, लेकिन ऐसे ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिससे किसान पराली न जलाएं। भले ही एनजीटी के दबाव में राज्य सरकारें पराली जलाने से रोकने के कदम उठाने की हामी भर देती हों, लेकिन बाद में यही अधिक देखने में आता है कि वे कभी संसाधनों के अभाव को बयान करने लगती हैं और कभी किसान हित की दुहाई देने लगती हैं।

चूंकि पराली को जलाने से रोकने के मामले में जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने से इन्कार किया जा रहा है इसलिए उत्तर भारत हर वर्ष सर्दियों के मौसम में पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आने को अभिशप्त है। यह समस्या इसलिए गंभीर होती जा रही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान धान की वे फसलें उगाने लगे हैं जिनमें कहीं अधिक अवशेष निकलता है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो उन्हें आपस में मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिनसे किसान पराली जलाने से बचें। बेहतर हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि पराली के निस्तारण का कोई कारगर तरीका अपनाने की जरूरत है। अगर यह दावा सही है कि किसानों को फसलों के अवशेष नष्ट करने वाले उपकरण सुलभ कराए जा रहे हैं तो फिर पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं यह कागजी दावा तो नहीं? सच जो भी हो, लगता यही है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था उससे कन्नी काट ली गई।

पर्यावरण रक्षा का संदेश

बापू की 150वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए झारखंड में महाअभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान और संकल्प से कदमताल करते हुए राज्य के स्कूली बच्चों ने भी गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण रक्षा एवं स्वच्छता का अनुकरणीय संदेश दिया है। दैनिक जागरण के जल संरक्षण अभियान से जुड़कर जलसैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे बच्चों ने इस मुहिम को पानी बचाने की मुहिम से भी जोड़ा है। बताने की जरूरत नहीं कि मृदा और जलस्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला प्लास्टिक जल संरक्षण की राह में भी बाधक है। प्लास्टिक से मुक्ति के इस संदेश को समाज में आगे बढ़ाने और इसे आत्मसात करने-कराने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसके लिए न सिर्फ माहौल बनाया जाना चाहिए बल्कि सतत निगरानी में यह काम आगे भी चलता रहना चाहिए। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने स्वच्छता का भी संदेश दिया था। इसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम समेत अन्य स्थानों पर खुद पहल की थी। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर बापू के सपने को पूरा कर स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और प्लास्टिक मुक्त झारखंड बनाएं। इस मुहिम को जन-जन का अभियान बनाने की घोषणा तभी सही मायने में अमल में आ सकेगी, जब पूरा देश दिल से प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प ले कर काम करे। हर स्तर पर इसकी पहल करनी होगी। जिस तरह स्कूली बच्चों ने गली-गली प्लास्टिक चुनकर स्वच्छता की अलख जगाई है, उससे हम सबों को सबक लेना चाहिए। जब ऐसी शपथ घर-घर में अंगीकार कर ली जाएगी तो कपड़े का झोला लेकर चलने और कचरा नहीं फैलाने से लेकर कचरा निस्तारण तक की आदत अपने आप बन जाएगी। प्लास्टिक से बनी दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करने पर भी गौर करते रहना होगा। सरकार और उसकी मशीनरी पर भी इसके लिए कड़े नियम बनाने और उसका अनुपालन कराने की महती जिम्मेदारी है। प्लास्टिक के कचरे का बढ़ता भंडार जिस तरह हवा, मिट्टी, पानी और पूरे वातावरण को प्रदूषित कर जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है, उससे निजात पाने के लिए आरपार की लड़ाई छेड़नी होगी। समय रहते नहीं चेते तो आनेवाले दिलों में परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

> प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को हमें अपनी भविष्य सुरक्षित रखने की जरूरी मुहिम के रूप में देखना चाहिए

असहमति के बाद भी करीब आता अमेरिका

हर्ष वी पंत

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में भले ही कुछ ठोस मसलों पर बात नहीं बनी हो, लेकिन वह भारत-अमेरिकी संबंधों में आई शिथिलता को दूर करने और विश्व समुदाय को साधने में सफल रहे

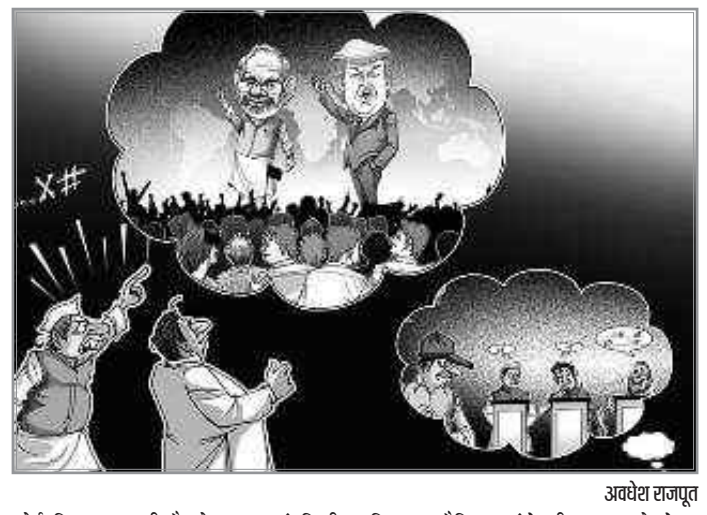

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे पर खासी टीका-टिप्पणियां हो रही हैं। यह स्वभाविक भी है। जहां उनके समर्थक इस दौरे को भारत के लिए बड़ी जीत करार दे रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री के आलोचकों का कहना है कि इस दौरे में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई, मगर इस बात पर किसी विवाद या बहस की कोई गुंजाइश नहीं कि अपने पूरे दौरे में प्रधानमंत्री मोदी फ्रंटफुट पर खेलते नजर आए और उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ भारत के हितों को वैश्विक मंच पर रखा। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति में परंपरागत रक्षात्मक रवैया बदला है। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान भी वह भारतीयों की आकांक्षाओं को मुखरता के साथ प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहे। अपने इस व्यस्त अमेरिकी दौरे में मोदी को चार भूमिकाएं निभानी थीं। सबसे पहले तो उन्हें अमेरिका के साथ विशेषकर व्यापारिक मोर्चे पर तल्खी को कम करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी अर्से से व्यापारिक मुद्दों को लेकर भारत पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह वाशिंगटन को आश्वस्त करें कि भारत परस्पर लाभ के लिहाज से अमेरिका के साथ ठोस मुद्दों पर सक्रियता से संवाद करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के साथ व्यापारिक तानेबाने को सुगम बनाने के लिए भारतीय अधिकारी विशेषकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ लगातार सक्रिय हैं। यहां तक कि ह्यूस्टन में अपनी रैली के दौरान खुद मोदी ने ट्रंप को बड़े जोरदार ढंग से लुभाने की कोशिश की। वहीं ट्रंप उस कार्यक्रम में स्वयं को भारत और भारतीय मूल के अमेरिकियों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कवायद का खाका मोदी ने ही खींचा था। बहरहाल इस दौरे में बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता नहीं हो सका। इसकी मुख्य वजह यही रही कि दोनों देश सूचना एवं संचार यानी आइसीटी उत्पादों पर कोई सहमति बनाने में नाकाम रहे, मगर इन वार्ताओं ने वाशिंगटन को यह भरोसा जरूर दिलाया कि अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर भारत बहुत गंभीर है। व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप का बयान दोनों देशों के बीच सहजता के स्तर की पुष्टि करता है।

मोदी के लिए दूसरी भूमिका यह थी कि वह अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों के समक्ष निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत का पक्ष मजबूती से रखें। उन्हें भारत की ऐसी पैरवी एक ऐसे समय में करनी थी जब देश में आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों के प्रमुखों के साथ ह्यूस्टन में और फिर मास्टरकार्ड, वीजा और वालमार्ट जैसी 40 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ न्यूयार्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में मोदी ने भारत में निवेश आकर्षण के पहलुओं को रेखांकित किया। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि निवेशकों को कोई दिक्कत आती है तो वह स्वयं निजी हस्तक्षेप करके उसका निदान करेंगे। मोदी ने भारत के लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और निश्चिंतता जैसे तमाम बिंदु गिनाए जो भारत की वृद्धि को धार दे रहे हैं और वैश्विक निवेशक भी इसका हिस्सा बनकर लाभ उठा सकते हैं। मोदी भारत के सबसे बेहतरीन ब्रांड अंबेसडर बने हुए हैं और वह भारत की पैरवी ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब तमाम लोगों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

मोदी के लिए तीसरी भूमिका अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमताओं को पुनः रेखांकित करने से जुड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में उन्होंने जिस तरह भारत के आमूलचूल परिवर्तनों को प्रकट किया वह उन व्यापक आकांक्षाओं के अनुरूप ही था जो दुनिया लगातार भारत से करती आ रही है। एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका और भारत के उदय को समायोजित करने के लिए नए वैश्विक ढांचे की दरकार को लेकर उनका भाषण तेजतर्रार और स्पष्टता लिए था। इस मंच पर मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीयवाद भारतीय सभ्यता के मूल्यों में स्वाभाविक रूप से सन्निहित है। वह केवल शक्ति संतुलन में भारत के हितों को लेकर की जाने वाली तिकड़म नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज किया। यहां तक कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से किए आह्वान में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना गवारा नहीं समझा। इससे भी महत्वपूर्ण उनका यह कहना रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली बहुध्रीवयता को अनिवार्य मानती है। उन्होंने यह कहते हुए दुनिया में बढ़ते संरक्षणवाद पर प्रहार किया कि 'हमारे पास यह विकल्प नहीं कि हम स्वयं को अपनी सीमाओं में समेटकर रखें।' यह कहकर उन्होंने ट्रंप की बहुध्रुवीयता की समाप्ति वाली अवधारणा को स्पष्ट रूप से खारिज किया।

आखिर में मोदी के लिए चौथी भूमिका यही थी कि वह जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत के पक्ष को रखने के साथ ही इस मसले पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार की काट करें। इसके लिए उन्होंने ह्यूस्टन रैली के मंच का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया और ट्रंप की मौजूदगी में यह संदेश दिया कि नई दिल्ली को यह नीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने कितने पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से इस फैसले को अंजाम दिया। इस सभा में मौजूद 50,000 भारतीय-अमेरिकियों द्वारा इस पर गर्मजोशी से दी गई प्रतिक्रिया से अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान को महसूस हुआ होगा कि अनुच्छेद 370 पर नई दिल्ली के निर्णय को भारतवंशियों का कितना जबरदस्त समर्थन हासिल है। मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विभिन्न मंचों पर भारत के पक्ष को बखूबी बयान किया। इस दौरान वह कई मिथ्या धारणाओं को दूर करने में सफल रहे।

स्पष्ट है कि मोदी के अमेरिकी दौरे में तमाम मसलों पर बात आगे बढ़ी और इस दौरान की गई तमाम कोशिशें सराहनीय कही जाएंगी। यह सही है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक गतिरोध पर तनाव कायम है और ट्रंप एक अनिश्चित एवं अस्थिर वार्ताकार बने हुए हैं, वहीं इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि अमेरिका में अभी भी पाकिस्तान के हमदर्द मौजूद हैं। मगर मोदी का दौरा इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं था। यह दौरा संबंधों में आई शिथिलता को दूर करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साधने पर केंद्रित था। इन दोनों मोर्चों पर मोदी प्रभावी रहे। अब पूरा दारोमदार भारतीय कूटनीति पर है कि मोदी के इस दौरे से बने बढ़िया माहौल को कैसे निरंतरता देकर उसे भलीभांति भुनाए।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

गीता के ज्ञान पर व्यर्थ का विवाद

प्रो. निरंजन कुमार

यह फिर साबित हुआ कि वामपंथी और उदारवादी बुद्धिजीवियों को भारतीय परंपरा-संस्कृति में से कुछ भी ठीक नहीं लगता

प्रसिद्ध चिंतक मारकस गार्वी लिखते हैं कि अपने अतीत, मूल और संस्कृति के ज्ञान के बिना व्यक्ति अथवा समाज एक जड़हीन वृक्ष की तरह है। अतीत की ओर देखने का अर्थ भविष्य से मुंह मोड़ना नहीं है, क्योंकि अतीत भविष्य की प्रशस्त राह बनाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वामपंथियों, छद्म उदारवादियों और औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त अंग्रेजीपरस्त बुद्धिजीवियों ने अपने गौरवशाली अतीत को न केवल हमेशा नकारा, बल्कि उसे हिकारत भरी दृष्टि से भी देखा। इसका ताजा उदाहरण है चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्स में भगवद्गीता को शामिल करने पर उठा विवाद। द्रमुक नेता स्टालिन और वामपंथी नेता सीताराम येचुरी के साथ-साथ कई बुद्धिजीवियों ने इसे आरआरएस और भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा बताकर इसके विरोध में विवाद खड़ा कर दिया। इसके कई पहलू हैं। एक तो यह कि इंजीनियरिंग कोर्स में दर्शनशास्त्र और भगवद्गीता का क्या औचित्य? दूसरे, भगवद्गीता के माध्यम से हिंदू धर्म को आरोपित किया जा रहा है। दर्शनशास्त्र ही पढ़ाना हो तो इसमें कुरान, बाइबिल आदि क्यों नहीं शामिल हों? यह भी कहा जा रहा है कि भगवद्गीता पलायनवाद को बढ़ावा देगी। एक आरोप यह भी है कि भगवद्गीता के माध्यम से संस्कृत द्वारा तमिल और द्रविड़ संस्कृति पर हमला है।

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्ना यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग में भगवद्गीता को शामिल किया। एआइसीटीई देश में इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा का नियमन करती है। उसके मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार इंजीनियरिंग में मानविकी और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। एआइसीटीई ने ऐसे 32 विषय सुझाए हैं जिनमें अन्ना विश्वविद्यालय ने 'भारतीय संविधान', 'अंग्रेजी', 'व्यावसायिक संचार', 'फिल्म मूल्यांकन बोध' और 'दर्शन और नैतिकता' जैसे छह कोर्स शुरू किए हैं। इनमें से कोई अनिवार्यता नहीं है, छात्र किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। फिर भी प्रश्न उठाया गया कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दर्शनशास्त्र या फिल्म मूल्यांकन-बोध आदि क्यों? दरअसल एक संतुलित और सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में ऐसे कोर्स बहुत सहायक होते हैं। विभिन्न नवीनतम शोधों में पाया गया है कि जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति में बौद्धिक गुणांक के अतिरिक्त भावात्मक गुणांक, सामाजिक गुणांक और विपरीत परिस्थिति गुणांक होना भी आवश्यक है। गीता या दर्शनशास्त्र अथवा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषय इसमें बहुत सहायक होते हैं। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए सामाजिक विज्ञान के कई विषय पढ़ने अनिवार्य हैं। अपने यहां भी आइआइटी में मानविकी का पूरा एक विभाग है।

एक आरोप यह भी है कि यह शिक्षा का भगवाकरण या हिंदुकरण है। यहां यह समझना जरूरी है कि भगवद्गीता बाइबिल या कुरान की तरह विशुद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसे एक दर्शन ग्रंथ के रूप में देखा जाता है जो कर्म और ज्ञान का संदेश देता है। महात्मा गांधी से लेकर प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक-दार्शनिक एल्डस हक्सले, अमेरिकी चिंतक एवं गांधीजी के दार्शनिक गुरु हेनरी डेविड थोरो, अमेरिकी वैज्ञानिक एवं परमाणु बम के जन्मदाता रॉबर्ट ओपेनहाइमर और स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोविश्लेषक कार्ल जंग और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भगवद्गीता के बड़े प्रशंसक रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि अन्ना विश्वविद्यालय में भगवद्गीता एक स्वतंत्र कोर्स के रूप में नहीं, बल्कि दर्शनशास्त्र का हिस्सा है जिसमें भारतीय और पश्चिमी दर्शन का मिश्रण है। इसमें सुकरात, प्लेटो और फ्रांसिस बेकन और मिशेल फूको पर अध्याय भी शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक देशों में इंजीनियरिंग आदि में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। दक्षिण कोरिया में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में ईसाई मजहब की शिक्षा अनिवार्य है। एक आरोप यह भी है कि भगवद्गीता के माध्यम से तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति पर संस्कृत और तथाकथित आर्य संस्कृति को थोपा जा रहा है। यह बेतुका आरोप है, क्योंकि खुद अन्ना यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यह कोर्स अनिवार्य विषय नहीं है। तब इसमें संस्कृत थोपने जैसी बात कहां से आती है?

फिर यह भी कि गीता को तमिल या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। दरअसल आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सियासी फायदे के लिए द्रमुक तरह-तरह की तिकड़म कर रही है। इसी क्रम में तमिल-संस्कृत अथवा द्रविड़-आर्य संस्कृति का नकली विवाद खड़ा कर रही है। यहां यह जानना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि जिस तमिल-संस्कृत का द्वंद्व पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में इंडो-यूरोपीय तुलनात्मक ऐतिहासिक भाषाविज्ञान और द्रविड़ भाषा विज्ञान के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ प्रो. थॉमस बरो का शोधकार्य 'लोनवर्डस इन संस्कृत' (1946) और 'कलेक्टेड पेपर्स ऑन द्रविड़ियन लिंग्विस्टिक्स' (1968) दर्शाता है कि संस्कृत के हजारों शब्द कुछ परिवर्तनों के साथ तमिल भाषा में शामिल हो चुके हैं और इसी तरह संस्कृत ने बड़ी संख्या में तमिल से शब्द ग्रहण किए हैं। भगवद्गीता को आर्य संस्कृति से जोड़ना और द्रविड़ संस्कृति को इससे अलग बताते हुए इस पर हमले का झूठा वितंडा खड़ा करना वामपंथी और छद्म उदारवादी बुद्धिजीवियों का पुराना शगल रहा है। इसी क्रम में ये आर्यों को बाहर से आया बताते हैं, जबकि हाल में हरियाणा के राखीगढ़ी की खोदाई में मिले नरकंकाल-अवशेषों के डीएनए अध्ययन में हार्वर्ड और प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के अध्येताओं ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि आर्य बाहर से भारत में आए थे।

वामपंथी व उदारवादी बुद्धिजीवियों को भारतीय परंपरा-संस्कृति में से कुछ भी ठीक नहीं लगता, जबकि भगवद्गीता का चिंतन सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। अमेरिकी चिंतक व गांधी जी के दार्शनिक गुरु हेनरी डेविड थोरो के इस कथन को ये लोग न भूलें कि वेद-उपनिषद के महान शिक्षण में संप्रदायवाद-अलगाव का कोई स्पर्श नहीं है। यह सभी युगों और राष्ट्रीयताओं के लिए है और महान ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कल और आज के बीच

कल के लिए हम कितना कुछ 'संभाल' कर रख देते हैं। अधिकांश लोग सोचते रहते हैं कि जो करना है, कल ही करना है। उनके इस कल-कल के चक्कर में कल कभी आ ही नहीं पाता। कल एक ऐसा सपना बनकर रह जाता है, जो कभी पूरा ही नहीं होता। हम कल और आज के बीच में ही झूलते रहते हैं। हम वर्तमान से कहीं ज्यादा कल में रहना-जीना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कल पर छोड़ दिए गए कार्य शायद ही कभी पूरे हो पाते हैं। कल हमारे लिए ऐसा खूबसूरत बहाना बनकर रह जाता है, जिसे हर कोई अपने करीब रखना चाहता है। जाहिर है कि कल से हर कोई अपने आज को आसान करना चाहता है। दरअसल यह आलस की भी निशानी होती है।

हालांकि ऐसा कहा जरूर गया है कि हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। जो करना है आज ही करना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो इस बात का ध्यान रखते हैं। साफ-सी बात है, जब हमारा आज ही व्यवस्थित नहीं होगा तो अपने कल को हम क्या खाक संवार पाएंगे। हम नहीं जानते कि कल पर टाल कर अपने आज का नुकसान कर रहे होते हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान-2 मिशन में हमारे वैज्ञानिकों को जो सफलता मिली है, वह कल पर काम टालने की प्रवृत्ति की बदौलत नहीं, बल्कि आज का काम आज ही करने की सोच और दृढ़-इच्छाशक्ति के कारण मिली है। विज्ञान आज के तर्कों के हिसाब से चलता है, वह हवा में तीर छोड़ने में विश्वास नहीं करता। कल क्या होगा, कैसा होगा इसे कल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। कल के सहारे जीवन नहीं गुजारा जा सकता है।

आज का कार्य अगर कल पर डाल देंगे तो शायद ही कोई देश या समाज तरक्की की राह पर चल पाएगा। जो भी करना है आज ही करना चाहिए। भविष्य का रास्ता वर्तमान की गली से ही गुजरता है। आज संवार लें तो कल बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मिली सफलताएं ही तो कल का सुख हमें देती हैं। भविष्य की बुनियाद वर्तमान में ही रखी जाती है।

अंशुमाली रस्तोगी

रामगंगा का गला घोंट रहा ई-कचरा

फिर से

> रामगंगा के घाटों पर ई-कचरे के रीसाइक्लिंग की गतिविधियों से निकले रसायन मिट्टी और भूमिगत जल प्रदूषित कर रहे हैं

आखिर आपका मोबाइल फोन या टीवी का रिमोट, कंप्यूटर या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए, पुराना हो जाए तो आप उसका क्या करते हैं? जाहिर है, हम उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं। देश भर में हम सबके घरों से निकले इस ई-कचरे का पचास फीसद हिस्सा उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद पहुंच जाता है। वही शहर जो कभी, पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर था। अब यह शहर भारत के ई-कचरे का सबसे बड़ा कबाड़खाना है। और इसका बुरा असर पड़ रहा है इसके बगल से बह रही बदकिस्मत नदी रामगंगा पर।

गंगा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है रामगंगा, जो उद्गम स्थल से दो अलग धाराओं के रूप में शुरू होती है। तब इसे पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा कहते हैं और पहाड़ों से यह मैदानों तक बहती आती है।

इस नदी के किनारे बढ़ती आबादी और उद्योगों की संख्या ने नदी की हालत पतली कर दी है। आइआइटी, रुड़की के वैज्ञानिकों ने नदी की सेहत का एक अध्ययन किया है। अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि रामगंगा नदी अपनी निचली धारा में बहुत अधिक प्रदूषित है। इस प्रदूषण में फ्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्सियम जैसे तत्वों के यौगिकों की मात्रा काफी अधिक है। समस्या की असली जड़ मुरादाबाद शहर का कबाड़ उद्योग है। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा है और यह ई-कचरे की रीसाइक्लिंग के लिए भी जाना जाता है। प्रशासन का मानना भी है कि देश में कुल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का पचास फीसद मुरादाबाद में आकर जमा होता है। और रोजाना शहर में ई-कचरे की 9 टन मात्रा जमा हो जाती है। रामगंगा के घाटों पर ई-कचरे के रीसाइक्लिंग की गतिविधियों से निकले रसायन जमीन में चले जाते हैं और इस तरह मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं।

असल में पारा और आर्सेनिक इंसानी सेहत के नजरिए से काफी जहरीले तत्व होते हैं। पारा अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए, जाहिर है जलीय जीवों और मछलियों के जरिए, तो इंसानी मस्तिष्क के कामकाज करने पर बुरा असर डालता है। इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज अभी मुमकिन नहीं हो पाया है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ई-कचरे का यह काम अधिकतर अवैध है जहां किसी किस्म के सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जाता इसलिए यह समस्या कहीं अधिक घातक है।

हालांकि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ई-कचरे के समाधान में उचित कार्रवाई न करने के एवज में 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है, पर इसका असर क्या होगा यह देखना बाकी है। फिलहाल रामगंगा में ई-कचरे की वजह से जमा हो रहे भारी धातुओं ने खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। इसके घातक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, गंगा की इस सहायक नदी की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। रामगंगा को साफ नहीं किया तो गंगा कभी साफ नहीं होगी।

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजित ठाकुर)

मेलबाक्स

पाकिस्तान की संकीर्ण मानसिकता

हम सबके प्रकाशपुंज हैं गांधी शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुधींद्र कुलकर्णी ने भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते मधुर करने के लिए पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह महात्मा गांधी की विचारधारा पर अमल करे। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए यह बताना जरूरी है कि महात्मा गांधी उसके बारे में कितना सोचते थे। गांधी जी ने एक समय पाकिस्तान को कंगाल होने से भी बचाया था। जब देश आजाद हुआ था, तब भारत के खजाने में जो राशि थी, उसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। और एक समझौते के आधार पर भी अभी पाकिस्तान को कुछ और राशि दी जानी थी, लेकिन उसकी कश्मीर को लेकर नापाक सोच सामने आने पर भारत ने उसकी बकाया राशि देने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सरकार जानती थी कि पाकिस्तान इस राशि का दुरुपयोग कश्मीर में जहर उगलने के लिए करेगा। जब गांधी जी को यह खबर मिली कि नेहरू और पटेल ने पाकिस्तान का 55 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया है तो वह बहुत नाराज हुए और उन्होंने कश्मीर समस्या को नजरअंदाज करते हुए दोनों नेताओं से कहा कि पाकिस्तान को उसके हक वाला पैसा तुरंत दे दिया जाए नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। नेहरू-पटेल ने बापू को पूरी स्थिति बताई, लेकिन वह नहीं माने। गांधी जी ने 13 जनवरी, 1948 को उपवास शुरू कर दिया। इस पर सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दे दिए गए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भले ही गांधी की विचारधारा का समर्थन किया हो, लेकिन जब तक हमारे देश के प्रति पाकिस्तान की संकीर्ण सोच नहीं बदलती, तब तक न तो भारत-पाकिस्तान के रिश्ते मधुर हो सकते हैं और न ही महात्मा गांधी का प्रकाशपुंज कपटी पाकिस्तान में उजियारा ला सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

दहेज की कुप्रथा

प्राचीन काल में राजा महाराजा तथा धनी लोग अपनी बेटियों की शादी में हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि प्रचुर मात्रा में दिया करते थे। धीरे-धीरे यह प्रथा हमारे समाज में फैल गई। समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष भी गुण बन जाता है। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा आज भी हमारे समाज में फल फूल रही है। कहा जाता है कि बेटी से बड़ा कोई धन नही, परंतु हमारा समाज अब भी इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। दहेज प्रथा के प्रति हमारे समाज के लोगों की सोच आज भी उजागर नही हो पायी है। बेटी पक्ष से बड़े दहेज की मांग करने पर लोग एक बार भी नही सोचते कि बेटी पक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा। दहेज प्रथा के बुरे परिणाम के बारे में सोच कर हर किसी की रूह कांपने लगती है, क्योंकि इतिहास ने दहेज प्रथा से तड़पती बेटियों की एक बड़ी लिस्ट बना रखी है। यह प्रथा एक बेटी के अरमानों को चूर-चूर कर देती है। यह प्रथा केवल अमीरों तक ही सीमित नही है, बल्कि गरीबों और मध्य वर्गियों का भी सरदर्द बन बैठी है। जब तक दहेज के प्रति लोगों की सोच नही बदलेगी तब तक बेटियों के साथ ये अन्याय होता रहेगा। सरकार ने दहेज के खिलाफ कानून तो बना रखे हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार में बैठे लोग चाहे नेता हों या अधिकारी वे भी दहेज का लेनदेन करना अपनी शान समझते हैं। जब तक शादियां दहेज मुक्त नहीं होंगी और दहेज वाली शादियों का लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, इस बुराई को रोकना मुश्किल है।

prashantyadav8948@gmail.com

खिलाड़ी को मिले मार्गदर्शन

जब कोई युवा खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनता है तो उसे अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। कोच व कप्तान का यह दायित्व बनता है कि वे नए युवा सदस्य का मार्गदर्शन करें, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रवैया विचित्र है। युवा क्रिकेटर ऋषभ पंत को जहां मार्गदर्शन की जरूरत थी वहीं आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया और परिणामतः उन्हें दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध खेले जा रहे पहले टेस्ट की टीम में नहीं चुना गया। बेशक महेंद्र सिंह धौनी महान खिलाड़ी हैं, लेकिन वे एक दिन में महान नहीं बन गए थे। यदि रिकार्ड देखा जाए तो ज्ञात होगा कि आरंभ में लगभग सभी खिलाड़ियों ने संघर्ष किया है। ऋषभ पंत का प्रदर्शन इतना बुरा भी नहीं र